गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 192
दि. 13.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, कुलगाम और सोपोर में जमात-ए-इस्लामी के 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

(जीएनएस)। कुलगाम/सोपोर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों ने एक और बड़ा अभियान चलाते हुए बुधवार को कुलगाम और सोपोर जिलों में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के 200 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस व्यापक कार्रवाई का उद्देश्य संगठन के बचे हुए नेटवर्क, फंडिंग चैनल और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह समाप्त करना बताया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुलगाम जिले में पिछले चार दिनों से यह अभियान लगातार जारी है और अब तक कुल 400 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली जा चुकी है। इनमें ओजीडब्ल्यू (Over Ground Workers), जेकेएनओपीएस नेटवर्क, पूर्व मुठभेड़ स्थल और सक्रिय या मारे गए आतंकवादियों के ठिकाने शामिल हैं। इस दौरान सुरक्षाबलों ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन और कई संदिग्ध सामग्री बरामद की है, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में अब तक लगभग 500 संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें से कुछ को निवारक कानूनों के तहत हिरासत में लेकर मट्टन (अनंतनाग) जिला जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान कुछ संदिग्धों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा,

लेकिन आतंकवाद और उसके सहयोगी नेटवर्क के प्रति "शून्य सहिष्णुता" की नीति में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

उधर, उत्तर कश्मीर के सोपोर में भी पुलिस ने बुधवार सुबह बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। सोपोर, ज़ैंगीर और राफियाबाद क्षेत्रों में एक साथ 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। विश्वसनीय खुफिया इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें यह जानकारी मिली थी कि प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े कुछ पुराने सदस्य फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं और गुप्त बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। सोपोर पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, संगठन से जुड़े दस्तावेज़, प्रचार सामग्री और संदिग्ध मुद्रित पर्चे जब्त किए गए हैं। इन सामग्रियों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये किन गतिविधियों से संबंधित हैं और इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के समर्थन में काम करने वाले हर तत्व के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां इस अभियान को आतंकवाद के सामाजिक, धार्मिक और वित्तीय आधार को ध्वस्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मान रही हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घाटी में किसी भी प्रकार की उग्रवादी गतिविधि या देशविरोधी प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का यह समन्वित अभियान यह भी संकेत देता है कि जम्मू-कश्मीर में अब सरकार का फोकस केवल आतंकवादियों के एनकाउंटर तक सीमित नहीं, बल्कि उनके पीछे की वैचारिक और वित्तीय जड़ों को समाप्त करने पर केंद्रित है। कुलगाम और सोपोर की यह संयुक्त कार्रवाई इसी रणनीति की झलक पेश करती है, जिसने घाटी में आतंक समर्थक तंत्र के लिए एक बड़ा झटका पैदा किया है।

बांग्लादेश में अवामी लीग के बंद के दौरान हिंसा की लपटों में ढाका, उपद्रवियों ने बसों में लगाई आग, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से बढ़ा तनाव

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और आसपास के जिलों में मंगलवार रात से हालात अचानक बिगड़ गए जब अवामी लीग द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएँ सामने आईं। प्रदर्शनकारियों और अज्ञात उपद्रवियों ने राजमार्गों पर खड़ी बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल फैल गया। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की 14 प्लाटून राजधानी और उसके आसपास के जिलों में तैनात कर दी हैं।

बीजीबी के प्रवक्ता शरीफुल इस्लाम ने बताया कि ढाका में कुल 12 प्लाटून और ढाका से सटे गाजीपुर व नारायणगंज जिलों में दो प्लाटून अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रमुख इलाकों जैसे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, धानमंडी-32, हवाई अड्डा क्षेत्र, अब्दुल्लापुर, काकरैल, शिशु अकादमी, उच्च न्यायालय परिसर और अबरार फहद एवेन्यू में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की चौकसी बढ़ा दी गई है।

जानकारी के अनुसार, यह हिंसा उस समय भड़की जब अवामी लीग ने देशव्यापी

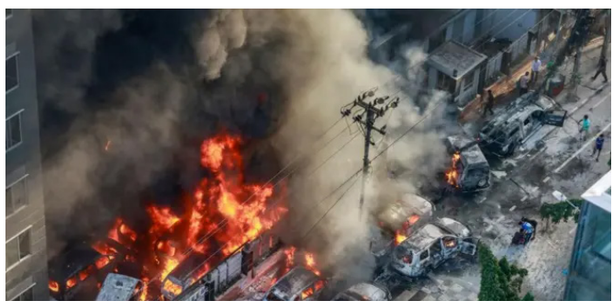

बंद का आह्वान किया था। बंद का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस बहुप्रतीक्षित फैसले से पहले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करना बताया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों से जुड़े एक मामले में 13 नवंबर को सुनाया जाना है।

अंतरिम सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार देर रात से ही राजधानी के कई हिस्सों में झड़पें हुईं। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, और पुलिस को उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की कि उपद्रवियों ने ढाका और गाजीपुर में तीन बसों में आग लगा दी।

पहली घटना भोगरा बाइपास के पास ढाका-तंगाइल राजमार्ग पर हुई, जहां खड़ी एक यात्री बस को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया। दूसरी घटना श्रीपुर उपजिला के बेरैड चाला क्षेत्र में दर्ज की गई, जबकि तीसरी आगजनी कालियाकोइर-नबीनगर राजमार्ग पर रात लगभग 10 बजे एक मिनी बस में की गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, हालांकि वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। हिंसा की खबर मिलते ही ढाका पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) की टीमें घटनास्थलों पर पहुंच गईं और कई संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक किसी संगठन ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ली है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में आम नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल है। कई इलाकों में दुकानें बंद हैं, यातायात आंशिक रूप से ठप है, और लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह बंद केवल आर्थिक या प्रशासनिक विरोध नहीं बल्कि देश में बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत है। एक ओर अवामी लीग अपने समर्थन आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसे "राजनीतिक दमन" का माहौल बताकर सरकार को घेरने में लगे हैं।

उधर, बीजीबी और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात कर दिए गए हैं। राजधानी के प्रमुख सरकारी भवनों, अदालत परिसर और मीडिया संस्थानों के आसपास सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है।

अमेरिका के दरवाज़े फिर खुले: ट्रंप ने बदला सुर, विदेशी प्रतिभाओं के महत्व को किया स्वीकार — भारतीय विशेषज्ञों में खुशी की लहर

(जीएनएस)। वॉशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय नीति और वैश्विक रोजगार जगत में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एच-1बी वीजा' को लेकर अपने पुराने सख्त रुख से हटते हुए पहली बार यह स्वीकार किया कि अमेरिका को विदेशी प्रतिभाओं की ज़रूरत है। लंबे समय से विदेशी पेशेवरों, विशेष रूप से भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों पर नकेल कसने वाले ट्रंप ने अब संकेत दिया है कि कुछ उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अमेरिका अपनी घरेलू क्षमता से आगे बढ़ने में असमर्थ है और उसे बाहरी कौशल की आवश्यकता है।

फॉक्स न्यूज को दिए गए एक विस्तृत साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, "अमेरिका को प्रतिभाशाली लोगों को अपने देश में लाना ही होगा। हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं हैं, और उन्हें तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रहे, तो हमें बाहरी बुद्धिमत्ता का स्वागत करना ही होगा।" यह बयान उस समय आया है जब हाल के वर्षों में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी पेशेवरों के लिए नीतियाँ काफी कठोर कर दी थीं। लेकिन अब यह बदलाव न केवल नीति परिवर्तन का संकेत है, बल्कि यह अमेरिका के भविष्य के आर्थिक

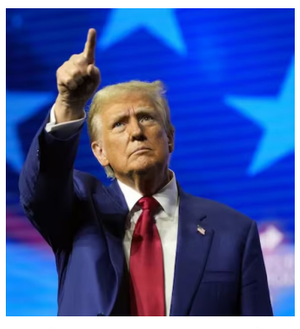

दृष्टिकोण की नई दिशा भी दिखाता है।

ट्रंप ने आगे कहा कि रक्षा, चिकित्सा, एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में स्थानीय कार्यबल सीमित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "कई अमेरिकी कामगार योग्य हैं, लेकिन कुछ तकनीकी क्षेत्रों में हमें विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की आवश्यकता है, और यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि प्रगति की आवश्यकता है।" यह बयान उनके पुराने 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे से विपरीत दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने विदेशी श्रमिकों पर कठोर प्रतिबंधों और वीज़ा सीमाओं की बात कही थी।

ट्रंप का यह नया रवैया उस पृष्ठभूमि में आया है जब उनके प्रशासन ने सितंबर 2025 में एच-1बी वीज़ा प्रणाली में एक विवादास्पद संशोधन किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल किए जाने वाले सभी नए वीज़ा आवेदनों के साथ 1 लाख अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय उस समय विदेशी कंपनियों, विशेषकर भारतीय आईटी उद्योग, के लिए भारी झटका साबित हुआ था। क्योंकि भारतीय कंपनियाँ हर साल हजारों कर्मचारियों को इसी वीज़ा के तहत अमेरिका भेजती हैं।

हालांकि बाद में अमेरिकी विदेश विभाग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह नया शुल्क केवल नई प्रविष्टियों पर लागू होगा, और पुराने वीज़ा धारकों या पहले से स्वीकृत आवेदनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद, उद्योग जगत में अस्थिरता और संशय बना रहा। अब ट्रंप के इस नवीनतम बयान से भारतीय पेशेवरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है।

अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने यह बदलाव एक गहन आर्थिक विश्लेषण के बाद किया है। हाल के वर्षों में अमेरिका में तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी देखने को मिली है, खासकर साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में। इस कमी के कारण कई अमेरिकी कंपनियों को प्रोजेक्ट धीमे करने पड़े या बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ा। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन हेरेल का कहना है, "अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता विदेशी प्रतिभाओं की वजह से बनी है। अगर एच-1बी वीज़ा पर रोके जारी रहतीं, तो अमेरिका अपनी नवाचार शक्ति खो देता।"

भारतीय दृष्टिकोण से यह घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल भारत से लगभग 70 प्रतिशत एच-1बी वीज़ा आवेदक होते हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और नवाचार में बड़ा योगदान देते हैं। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियाँ अपने हजारों इंजीनियरों को अमेरिकी परियोजनाओं पर काम करने भेजती हैं। इसलिए ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में राहत और उत्साह दोनों का माहौल है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था की व्यावहारिक आवश्यकता है, जिसे ट्रंप अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप के इस बयान का एक राजनीतिक पहलू भी है।

लातेहार में पांच लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव ने किया सरेंडर, पुलिस की अपील पर मुख्यधारा में लौटे दो नक्सली

(जीएनएस)। लातेहार। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम को बुधवार को बड़ी सफलता मिली जब जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के दो सक्रिय उग्रवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक, ब्रजेश यादव, पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। उसने अपने सहयोगी अवधेश लोहरा के साथ लातेहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के दौरान पलामू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शैलेंद्र कुमार सिन्हा और लातेहार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुमार गौरव मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने उग्रवादियों को माला पहनाकर समाज की मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत किया और उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सरेंडर करने वाला उग्रवादी ब्रजेश यादव गुमला जिले का रहने वाला है और लंबे समय से जनमुक्ति परिषद के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय था। वह संगठन का ज़ोनल कमांडर बताया जाता है और उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। दूसरा उग्रवादी अवधेश लोहरा लातेहार के हेरहंज क्षेत्र का निवासी है और संगठन में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत था।

आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि झारखंड सरकार ने उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए जो नई दिशा नीति लागू की है, उससे जंगलों में सक्रिय नक्सली बड़ी संख्या में समाज की मुख्यधारा की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि केवल वर्ष 2025 में अब तक लातेहार जिले में कुल 21 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो किसी भी जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह इस बात का संकेत है कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई, विकास योजनाओं की पहुँच और जनजागरूकता अभियानों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है।

लातेहार के एसपी कुमार गौरव ने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई से जिले में नक्सलवाद की जड़ें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में जिले में चार से पाँच नक्सली ही बचे हैं, जिन पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। उन्होंने कहा कि जो भी उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें सरकार पूरा सहयोग देगी। सूत्रों ने बताया कि ब्रजेश यादव ने सरेंडर से पहले पुलिस को संकेत दिया था कि वह हथियार छोड़ना चाहता है। लगातार चल रही सर्च ऑपरेशनों, बढ़ते पुलिस दबाव और संगठन के भीतर असहमति के कारण उसने यह निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के साथ ही उसने अपने हथियार और गोला-बारूद भी पुलिस को सौंप दिए।

आईजी सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा केवल नक्सलियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें पुनः समाज में स्थापित करना है। आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी बल्कि उन्हें पुनर्वास योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों से भी जोड़ा जाएगा।

भारत-अमेरिका समुद्री साझेदारी में नया अध्याय: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी अमेरिका की यात्रा पर रवाना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग होगा और मज़बूत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक समुद्री संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी सोमवार को अमेरिका की छह दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। यह यात्रा 12 से 17 नवंबर तक चलेगी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल, रणनीतिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझे हितों की रक्षा को और मज़बूत करना है। एडमिरल त्रिपाठी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और वैश्विक समुद्री सुरक्षा का संतुलन लगातार चुनौती के दौर से गुजर रहा है। भारत और अमेरिका दोनों इस क्षेत्र में स्वतंत्र और खुले समुद्री मार्गों को बनाए रखने के पक्षधर हैं, और यही साझा दृष्टिकोण दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार बनाता है। सूत्रों के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी अमेरिका में अपने समकक्ष वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। वे अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान (INDOPACOM) के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापारो, अमेरिकी प्रशांत बेड़े (PACFLT) के कमांडर एडमिरल स्टीफन टी. कोहलर तथा पेंटागन के शीर्ष रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत-अमेरिका नौसेनाओं के बीच परिचालनिक सहयोग, समुद्री क्षेत्र में सूचना साझाकरण, और संयुक्त मिशनों की समन्वय प्रक्रिया पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी अमेरिकी नौसेना के कई प्रमुख नौसैनिक अड्डों और प्रशिक्षण संस्थानों का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें नवीनतम नौसैनिक तकनीक, उन्नत हथियार प्रणालियों और सामरिक प्रशिक्षण ढांचे का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। इन दौरों का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमताओं को आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त बनाना और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों के स्तर को और ऊँचा उठाना है।

भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों में नौसैनिक सहयोग कई गुना बढ़ा है। दोनों देश "मालाबार" जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक-दूसरे की क्षमताओं को साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की बैठकों में भी हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर गहन संवाद होता है, जिसका केंद्र बिंदु चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को संतुलित करना है।

नौसेना प्रवक्ता के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी की यात्रा से "दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी भरोसा और समझ और गहरी होगी। यह यात्रा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन, समुद्री व्यापार की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

भारत ने हाल के वर्षों में समुद्री क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ी है और अमेरिका सहित अन्य मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत-अमेरिका नौसेना सहयोग केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोनों देश समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता अभियानों में भी साथ काम कर रहे हैं।

संपादकीय

बेमौत न मरें यात्री

विकास के नाम पर हमने सरपट वाहन दौड़ने वाली सड़कें तो बना दी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि यात्रा दुर्घटनाओं से निरापद कैसे रहे। यह हृदय विदारक होता है कि सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों, ट्रकों की अराजकता तथा राजमार्ग के अवरोधों के चलते परिवार के परिवार असमय काल कवलित हो जाते हैं। तंत्र की चतुराई ये होती है कि मुआवजे और दुर्घटना की फौरी जांच की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन सड़क दुर्घटना के मूल कारणों की तह तक नहीं पहुंचा जाता है। इन हादसों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। आए दिन खबर आती है कि तेज गति से आता कोई वाहन सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया और अनेक निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दो सप्ताह में दुर्घटना के कारणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस भीषण दुर्घटना के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए हैं। दरअसल, इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हादसे की वजह सड़क के किनारे गलत ढंग से खड़ा ट्रक बना। जिससे यात्रियों से भरा तेज गति से आता एक टेम्पो ट्रेवलर टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि इसमें चार बच्चों तथा दस महिलाओं समेत पंद्रह लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए। आमतौर पर किसी भी बड़े हादसे में शिकार हुए यात्रियों की संख्या का ही जिक्र होता है और सरकार मुआवजे की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। अधिक से अधिक हमारे विमर्श का मुद्दा यह होता है कि दोषी कौन था? कौन सा ड्राइवर लापरवाही से वाहन चला रहा था, वह नशे में था या उसे नींद की झपकी लग गई। या फिर वाहन में तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ।

लेकिन वास्तव में हम उन तकनीकी व वास्तविक खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। एक ओर जहां सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई चूक होती हैं, वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीब बने ढाबे भी होते हैं, जहां अकसर ट्रक चालक अपने वाहन गलत ढंग से खड़े कर देते हैं। लेकिन हर हादसे में कहीं न कहीं ऐसे कारण जरूर होते हैं, जो दुर्घटना की तात्कालिक वजह बनते हैं। लेकिन अकसर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा करने की वजह से भविष्य में ऐसी ही दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की आशंका बलवती होती है। यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह टोल संग्रह केंद्रों के जरिये टैक्स तो खूब वसूले जाते हैं, लेकिन राजमार्गों को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने के लिये गंभीर प्रयास नहीं होते। कुकरमुत्तों की तरह सड़कों का अतिक्रमण करते ढाबों पर लगाम नहीं लगायी जाती। गंभीरता से पड़ताल नहीं होती है कि क्या सड़क निर्माण में ठेकेदार ने सभी तकनीकी मानकों का पालन किया है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये नियमित जांच-पड़ताल की जाती रहे। ताकि निर्दोष लोगों के बेमौत मरने का सिलसिला खत्म हो सके। इन विभागों व मंत्रालयों का जिम्मा सिर्फ टोल वसूलना ही नहीं है बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना भी इनकी जवाबदेही है। निश्चित रूप से सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा उसे दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये उच्च सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन भी उतना जरूरी है। इसके अलावा सख्त कानून व निगरानी के जरिये ट्रकों को सड़क के किनारे खड़े करने पर रोक लगायी जाए। देश में सैकड़ों लोगों की मौत सड़क के किनारे गलत तरीके से खड़े ट्रक से वाहनों के टकराने से होती है, लेकिन दोषी ट्रक चालक को कड़ी सजा नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को भी गति सीमा में रहने तथा अन्य सावधानियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकारों का दायित्व भी बनता है कि राजमार्गों पर रफ्तार की सीमा के नियमन के साथ बाधामुक्त सफर भी सुनिश्चित करें।

सतत जागरूकता से बचेगी जनतंत्र की गरिमा

> “ राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों-मर्यादाओं का तकाजा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी शक्ति को पहचाने।

बिहार के चुनाव परिणाम पर ‘रेवड़ी’ का क्या और कितना असर पड़ता है यह तो मतपत्रों की गणना के बाद ही पता चलेगा, पर यह एक खुला रहस्य है कि हमारे राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि देश का मतदाता रेवड़ियों से रिझाया जा सकता है। देखा जाये तो एक तरह से यह देश के मतदाता का अपमान ही है कि उसके बारे में ऐसी धारणा बन रही है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति अचानक बन गयी है, अर्से से हमारे राजनीतिक दल इस रेवड़ी- संस्कृति का सहारा लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करते रहे हैं। शुरुआती दौर में यह काम चोरी- छिपे ढंग से होता था। मतदान से पहले की रात को न जाने क्या-क्या बंटता था मतदाताओं के बीच। अब भी ऐसा होता है, पर अब और भी रास्ते अपना लिये गये हैं, मतदाताओं को ‘खरीदने’ के– उदाहरण के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर बिहार के ‘सुशासन बाबू’ ने राज्य की लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को दस-दस हज़ार रुपये नकद बांट दिये। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसे प्रयोग हो चुके हैं। यही सब देखते हुए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खैरात बांटकर चुनाव जीते जा सकते हैं? भले ही कुछ राजनीतिक-विश्लेषक यह कहते रहें कि ऐसा नहीं हो सकता, पर इस धारणा से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे राजनेता यही मानते हैं कि खैरात काम आती है। अब तो हमारे सत्ताशीर्ष भी यह मान चुके लगते हैं कि चुनाव के अवसर पर रेवड़ियां बांटना ग़लत नहीं है!

बात सिर्फ रेवड़ी-संस्कृति तक सीमित नहीं है। चुनाव जीतने के लिए जिस तरह जाति और धर्म का सहारा लिया जा रहा है, वह एक तरह से हमारे लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाना ही है। जातियों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और धर्म की दुहाई देकर मतदाता को भ्रमित करने की कोशिशें बिहार के इस चुनाव प्रचार में लगातार हुई हैं। यहीं यह बात भी गौर करने लायक है कि चुनाव में ठोस मुद्दे उठाने के बजाय किसी ‘जंगल राज’ और वोटों की कथित ‘चोरी’ जैसी बातों का सहारा लेना राजनीतिक दलों को कहीं अधिक उपयोगी लगा है।

सत्तारूढ़ पक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी उपलब्धियों को आधार बनाकर मतदाता के समक्ष वोट मांगने जायेगा। पर देखा यह गया है कि सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष की बीस साल की पुरानी सरकार के ‘जंगल-राज’ का डर दिखाकर वोट पाने की उम्मीद कर रहा है। यह मान भी लें कि लालू-राबड़ी की सरकार का कथित जंगल-राज बहुत बुरा था, तब भी यह सवाल तो उठता ही है कि आज की युवा पीढ़ी को दो दशक पुराने उस अनुभव के आधार पर कोई निर्णय लेने के लिए कैसे कहा जा सकता है? विपक्ष से यदि कोई सवाल किया जाता है तो वह यह होना चाहिए कि उसके पास शासन का बेहतर विकल्प क्या है? यह मतदाता का अपमान नहीं तो और क्या है कि बिहार की वर्तमान सरकार की दस हज़ार रुपये की ‘रिश्वत’ के मुकाबले में विपक्ष तीस हज़ार रुपये नकद देने का प्रलोभन दे रहा है?

चुनाव जनतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होते हैं। रेवड़ियों, रिश्वत और घिसे-पिटे आरोपों के सहारे चुनाव जीतने की कल्पना ही इस उत्सव की गरिमा, महत्ता और पवित्रता को नष्ट कर देती है। यह सचमुच हैरानी की बात है कि नीतियों और नीयत के बजाय समाज को बांटने वाले नारों को चुनाव जीतने का आधार बनाया जाता है।

चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि सुदृढ़ जनतंत्र की दुहाई देने वाले देश में घटिया मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना अपने आप में किसी शर्म से कम नहीं है। सत्तारूढ़ पक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा बीस साल पुरानी सरकार की कथित विफलता थी और विपक्ष ने भी ठोस वैकल्पिक नीतियों को सामने रखने के बजाय ‘वोट चोरी’ जैसे कमजोर मुद्दे को अपना हथियार बनाया। विपक्ष ने बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे को उठाया अवश्य, पर मतदाता में यह विश्वास नहीं जगा पाया कि वह बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था दे सकता है। इसी तरह सत्तारूढ़ पक्ष का ‘घुसपैठियों’ वाला मुद्दा भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं लगा। वह इस सवाल का जवाब देने में भी विफल रहा कि उसके इक्कीस साल के शासन में वह घुसपैठियों को देश से निकाल क्यों नहीं पाया? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि इतने सारे घुसपैठिये देश में आ कैसे गये? इस सवाल का जवाब देश के गृहमंत्री को देना था, पर उनके पास जवाब था ही नहीं! हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष भी उस मज़बूती के साथ इस सवाल को नहीं उठा पाया, जो इस मुद्दे का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी थी।

चुनाव-परिणाम भले ही कुछ भी हों, लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनाव-प्रचार के दौरान कुल मिलाकर घटिया रण-नीति का ही परिचय दिया है। जनतंत्र की सफलता का तकाज़ा है कि स्वस्थ राजनीति की संभावनाओं को साकार बनाने की दिशा में कुछ ठोस सोचा जाये, कुछ ठोस किया जाये। यह दुर्भाग्य ही है कि ‘ठोस’ के नाम पर हमारे पास घटिया शब्दावली, घटिया नारे और घटिया तौर-तरीके हैं।

बात सिर्फ बिहार के इन चुनावों तक ही सीमित नहीं है। हमारी राजनीति में सब जगह यह गिरावट आई है। एक तरह की गुरिल्ला शैली अपना ली है राजनेताओं ने– झपट्टा मार कर कहीं निकल जाओ वाली शैली। कुछ भी कह कर, कुछ भी कर के उसे भुला देना इस शैली की विशेषता है। मान लिया गया है कि मतदाता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। राजनेताओं की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना ही चाहिए कि जुमलों के सहारे चुनाव जीता जा सकता है। राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों- मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी शक्ति को पहचाने। यह चिंता की बात है कि स्वस्थ राजनीति की जगह घटिया जुमलों वाली बीमार राजनीति पर हावी होती जा रही है। मान लिया गया है कि युद्ध और प्यार की तरह राजनीति में भी सब कुछ जायज है। चुनाव-दर-चुनाव यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजनेताओं के इस विश्वास के खोखलेपन को उजागर करना ही होगा कि वे जो कहेंगे-करेंगे जनता उसे स्वीकार कर लेगी।

सतत जागरूकता जनतंत्र के बने रहने की सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी शर्त है। हमारी राजनीति के झंडाबरदार इस शर्त को झुठलाने पर लगे हैं। बिहार के इस चुनाव-प्रचार के दौरान राजनीतिक घटियापन का एक कीर्तिमान ही स्थापित हुआ है। चुनाव-परिणाम चाहे कुछ भी हों, इस बात की चिंता तो देश के जागरूक नागरिक को करनी ही होगी कि हमारी राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है–इस गिरावट को रोकना ही होगा।

प्रेरणा

सपनों से ऊँची उड़ान: जीन हार्पर की अटूट इच्छा

नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे-से किसान गांव की मिट्टी में जन्मी एक नन्ही-सी बच्ची थी—जीन हार्पर। खेतों में काम करते हुए उसके पिता अकसर आसमान की ओर देखते और कहते, “देखो जीन, वो बादल कैसे तैर रहे हैं!” छोटी जीन उन बादलों को देखते-देखते ही कल्पना करने लगी कि काश एक दिन वह भी आसमान में उड़ सके। उसे नहीं पता था कि उसकी यह मासूम कल्पना आने वाले वक्त में उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना बन जाएगी।

बचपन के दिन संघर्षों से भरे थे। परिवार के पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन जीन के चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी — वही चमक जो किसी के भीतर के सपनों से पैदा होती है। वह पढ़ाई में औसत थी, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था — उड़ने की चाह, कुछ बड़ा करने की हिम्मत।

एक दिन स्कूल में उनकी टीचर ने बच्चों से पूछा, “बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?” कक्षा में तरह-तरह के जवाब आए — कोई डॉक्टर, कोई अध्यापक, कोई नर्स, कोई दुकानदार। लेकिन जब जीन की बारी आई, तो उसने बिना झिझके कहा, “मैं पायलट बनना चाहती हूँ।” यह सुनकर पूरी कक्षा हँस पड़ी। टीचर ने मुस्कराते हुए, लेकिन थोड़े व्यंग्य में कहा, “जीन, तुम्हारा सपना परियों की कहानी जैसा है। महिलाएं पायलट नहीं बन सकतीं।”

वह एक पल जीन के जीवन का सबसे कठिन पल था। उसके सपनों पर जैसे किसी ने पहरा लगा दिया हो। उसने अपनी किताबें बंद कर दीं, चुपचाप बैठ गई और उस दिन के बाद कभी अपने पायलट बनने की बात किसी से नहीं की। धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी टीचर सही थीं। वह एक साधारण लड़की थी — किसान की बेटी, और एक महिला — शायद उड़ान उसके लिए नहीं बनी थी।

समय बीतता गया। जीन हाईस्कूल में पहुंची। जीवन सामान्य चल रहा था, पर उसके भीतर कहीं वो दबा हुआ सपना अब भी सांस ले रहा था। एक दिन उसकी नई अंग्रेजी शिक्षिका, डोरोथी स्लेटन, ने पूरी कक्षा को एक असाइनमेंट दिया — “लिखो कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।” जीन की उंगलियाँ पेंसिल पर ठहर गईं। उसके मन में वही पुराना सपना उभर आया — आसमान, बादल और हवाई जहाज। लेकिन जैसे ही वह लिखने लगी, उसे अपनी पुरानी शिक्षिका की वह कठोर बात याद आ गई। डर और निराशा ने उसे फिर घेर लिया। उसने पन्ने पर लिखा — “मैं वेट्रेस बनना चाहती हूँ।”

अगले दिन डोरोथी स्लेटन ने सभी बच्चों की कॉपियाँ देखीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, “मुझे लगता है कि तुम सबने सच्चे मन से नहीं लिखा। फिर से सोचो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, और वही लिखो जो तुम्हारे सपने की आवाज़ है।” ये शब्द जैसे जीन के भीतर बिजली की तरह गूंजे। उसकी आंखों के सामने उसका वही पुराना सपना नाच उठा — नीला आसमान, उड़ते पंछी, और उसके हाथों में जहाज़ का कंट्रोल। उसने पेंसिल उठाई, पुराने डर को झटक दिया, और फिर लिखा — “मैं पायलट बनना चाहती हूँ।”

डोरोथी स्लेटन ने उसकी कॉपी पढ़ी और मुस्कराईं। उन्होंने कहा, “जीन, अगर तुम इस सपने को दिल से चाहो, अगर तुम्हारा जुनून सच्चा हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने विश्वास को कभी मरने मत देना।” यह वाक्य जीन के जीवन का turning point बन गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सपने पर विश्वास जताया था।

इसके बाद जीन ने ठान लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह उड़ान भरकर रहेगी। उसने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। वह खुद को हर दिन साबित करना चाहती थी कि वह कर सकती है। समाज के ताने, पैसों की तंगी, परिवार की सीमित आय — हर मुश्किल के बावजूद उसने अपने कदम नहीं रोके। वह हवाई जहाजों के बारे में पढ़ती, मॉडल बनाती, और हर रोज़ अपने सपनों को और मजबूत करती गई।

आखिरकार, वर्षों की मेहनत के बाद, वह दिन आया जब जीन हार्पर ने अपनी पहली उड़ान भरी। वह एक प्राइवेट पायलट बन चुकी थी। वह भावना उसके लिए वर्णन से परे थी — जैसे किसी कैदी को पहली बार खुला आसमान मिल गया हो। लेकिन जीन यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने आगे प्रशिक्षण लिया, हर बाधा को पार किया, और 1978 में यूनाइटेड एयरलाइन्स में नौकरी पाई। उस समय यह एक ऐतिहासिक पल था — क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइन्स ने पहली बार तीन महिला पायलटों को नियुक्त किया था, और उनमें से एक थीं — जीन हार्पर।

उसके बाद उन्होंने बोइंग 737 की कप्तान बनकर दिखाया कि सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दिल में सच्चा जुनून हो तो वह साकार होता ही है। आज उनकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जिन्हें कभी कहा गया कि “तुम नहीं कर सकतीं।”

जीन हार्पर ने दुनिया को यह सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने साबित किया कि लिंग, गरीबी या सामाजिक नियम किसी के सपने की उड़ान को रोक नहीं सकते। अगर कोई अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखता है, तो किस्मत भी झुककर सलाम करती है।

जीन की कहानी सिर्फ एक लड़की की जीत की कहानी नहीं है — यह उस हर इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी किसी के शब्दों से टूट गया, लेकिन फिर भी खुद को समेटकर उठ खड़ा हुआ। उसने हमें यह सिखाया कि सपनों से ऊँची कोई उड़ान नहीं होती, और जब मन में विश्वास हो, तो आसमान भी सीमा नहीं रहता।

अभी खत्म नहीं हुआ आतंक के खिलाफ युद्ध, दुश्मन भले ही कुछ कमजोर हो गया है, फिर भी वह वार करने में सक्षम

दिल्ली में लाल किले के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट ने फिर याद दिला दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने बाद यह आतंकी घटना इसकी पुष्टि करती है कि लड़ाई बस एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। दुश्मन हालांकि कमजोर हो गया है, फिर भी वार करने में सक्षम है। चिंताजनक बात यह है कि लाल किले की आतंकी घटना की साजिश बहुत सावधानी से रची गई।

विस्फोट से कुछ घंटे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद की दो रिहायशी इमारतों में लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। इनमें 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भी था। यह एक ऐसा उर्वरक होता है, जिसे आसानी से एक घातक बम में बदला जा सकता है। इस बरामदगी ने संभवतः एक और भी बड़ी त्रासदी को टाल दिया।

आतंकवाद के इस कृत्य में डाक्टरों की संलिप्तता यह बताती है कि कट्टरपंथ अब विश्वविद्यालयों, अस्पतालों जैसी उन जगहों में भी घुस रहा है, जिन्हें कभी सुरक्षित माना जाता था। लाल किला विस्फोट कांड की शुरुआत बीते 27 अक्टूबर को हुई, जब श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को डा. आदिल की पहचान करने में मदद मिली, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।

जब जांचकर्ताओं ने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कालेज में उसके लाकर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से एक असाल्ट राइफल मिली। उससे पूछताछ के दौरान पुलिस को फरीदाबाद में छिपे विस्फोटकों का एक जखीरा मिला, जिससे यह उजागर हुआ कि यह नेटवर्क कश्मीर से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस नेटवर्क के तार भारत की सीमाओं से परे भी जुड़े रहे हैं। आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान में सक्रिय थे। इस मामले में एक अन्य आतंकी अल फलाह विश्वविद्यालय के डा. मुजम्मिल शकील को भी गिरफ्तार किया गया। विस्फोटकों से लदी कार भी एक डाक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध आत्मघाती हमलावर दिल्ली में घुस आया था और उसने गाड़ी एक मस्जिद के पास खड़ी कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जब कार खड़ी थी, तब वह एक बार भी उससे बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि वह या तो निर्देशों का इंतजार कर रहा था या अपने लक्षित लक्ष्य का। जांचकर्ताओं का मानना है कि फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों से समूह में दहशत फैल गई होगी। फंसने का अहसास होने पर उमर मोहम्मद ने हताशा या घबराहट में बम विस्फोट कर दिया होगा। हो सकता है कि उसके संचालक ने उसे जिंदा पकड़े जाने के बजाय आत्मघाती हमला करने के लिए राजी किया हो। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि चरमपंथी समूह युवा शिक्षित दिमागों को यह विश्वास दिलाकर प्रभावित करते हैं कि शहादत एक महान कार्य है। एक बार फिर सुराग पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जैसे आतंकी समूहों को एक साथ लाने के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य भारत में आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करना और जम्मू-कश्मीर से परे भी अशांति फैलाना है। दिल्ली में विस्फोट के समय से पता चलता है कि यह आपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए था, जो भारत का सफल आतंकवाद-रोधी अभियान था।

पाकिस्तान की नई आक्रामकता वैश्विक राजनीति से भी जुड़ी हुई प्रतीत होती है। हाल में उसने मध्य एशिया में अपनी स्थिति का रणनीतिक लाभ उठाकर अमेरिका के साथ रिश्ते फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की है। जब भी पाकिस्तान को वैश्विक समर्थन मिलता है, वह उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत को उकसाने के लिए करता है। हालांकि आज भारत पहले जैसा नहीं रहा। आतंकवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रिया अब धीमी या रक्षात्मक नहीं रही। आपरेशन सिंदूर इसका प्रमाण था कि भारत आत्मविश्वास और सटीकता के साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार है, फिर भी लाल किला विस्फोट दर्शाता है कि आतंकियों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं। अब वे छोटे, छिपे हुए ठिकानों में काम करते हैं और आम जिंदगी में घुल-मिल जाते हैं, जिससे पुलिस के लिए समय रहते उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। सुरक्षा, सतर्कता केवल जम्मू-कश्मीर या दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में होनी चाहिए। आतंकियों के पास से बरामद विस्फोटकों की विशाल मात्रा विनाश के संभावित पैमाने को उजागर करती है। इससे इस आशंका को बल मिलता है कि कई समन्वित विस्फोटों की योजना बनाई गई हो सकती है। इसलिए खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में निगरानी कड़ी करना और अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार करना महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को खुद को आतंकवाद के शिकार के रूप में पेश करते हुए गुप्त रूप से उसका समर्थन करने वाले पाकिस्तान के दोहरे खेल का पर्दाफाश करना भी जारी रखना चाहिए। जो देश अभी भी पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी सहयोगी मानते हैं, उन्हें उसके वास्तविक रिकार्ड की याद दिलानी चाहिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और एफएटीएफ जैसे वैश्विक मंचों का उपयोग आतंकवाद को पनाह देने या उसे वित्तपोषित करने वाले देशों के खिलाफ सख्त अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए करना चाहिए। भारत को अपने अगले कदमों की योजना बनाते समय तत्काल सैन्य या जवाबी कार्रवाई से आगे बढ़ना चाहिए। आज आतंकवाद-निरोध के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत कूटनीति, उन्नत रक्षा और खुफिया प्रणालियां, आंतरिक सामाजिक सामंजस्य और सबसे बढ़कर, अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति शामिल है। लाल किले की घटना इसकी भी याद दिलाती है कि खतरा अभी भी हमारे बीच छिपा है और कमजोरी तथा विभाजन के क्षणों का इंतजार कर रहा है। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस, सशस्त्र बलों या खुफिया एजेंसियों की नहीं, बल्कि हर भारतीय की लड़ाई है। सरकार और विपक्ष को एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए।

अभियान

रोटी का रहस्य: आटे की हर लकीर में छिपा है सुख, समृद्धि और कर्म का अद्भुत विज्ञान

भारतीय संस्कृति में रोटी को केवल भोजन नहीं, बल्कि अन्न देवता का प्रसाद माना गया है। यह वह अन्न है जो हमारी धरती माता की कोख से उत्पन्न होता है और सीधे हमारे जीवन की ऊर्जा बनता है। हमारे पूर्वजों ने रोटी को लेकर जो नियम और परंपराएँ बनाई थीं, वे केवल मान्यताएँ नहीं थीं — वे प्रकृति, ऊर्जा और कर्म के गहरे विज्ञान से जुड़ी हुई थीं। लेकिन आधुनिकता की भागदौड़ में हममें से कई लोग इन्हें अंधविश्वास समझकर भूल चुके हैं। परंतु यह भूलना, वास्तव में अपने जीवन की शुभता और घर की बरकत को खो देना है।

कहा जाता है कि रोटी बनाते समय मन का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि रोटी बनाते हुए मन में क्रोध, थकान या नकारात्मक विचार हों, तो वह ऊर्जा रोटी के माध्यम से पूरे परिवार में फैलती है। इसलिए पुराने समय में माताएँ या दादियाँ रोटी बनाते समय भजन गुनगुनाती थीं, ताकि उस अन्न में शुभ कंपन समा जाएँ। उनके लिए रोटी बनाना केवल रसोई का काम नहीं, बल्कि एक पूजन क्रिया थी। यही कारण था कि उस युग के घरों में प्रेम, शांति और संतोष का वातावरण स्वाभाविक रूप से बना रहता था।

वास्तु शास्त्र कहता है कि रोटी कभी भी गिनकर नहीं बनानी चाहिए। यह बात सिर्फ मान्यता नहीं, एक गहरा प्रतीक है। जब हम रोटी गिनकर बनाते हैं, तो हम अन्न को “सीमित संसाधन” मान लेते हैं, और यही अभाव की भावना हमारे जीवन में उतर आती है। जो अन्न गिना जाता है, वहाँ कभी बरकत नहीं टिकती। जबकि जो अन्न प्रेम और सहजता से बनता है, वहाँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में माताएँ यह कहा करती थीं — “रोटी गिनकर नहीं, दिल से बनाओ।” क्योंकि अन्न वही फल देता है जो भावना से बनाया जाए।

कई बार देखा जाता है कि आटा गूंथते समय महिलाएँ उंगलियों के निशान छोड़ देती हैं। शास्त्रों में यह दोष माना गया है। कहते हैं कि जब आटे पर ऐसे निशान बन जाते हैं, तो वह पिंड के समान प्रतीत होता है, जो मृत्यु और पीड़ा का प्रतीक है। ऐसे आटे से बनी रोटी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और

घर में अनचाही समस्याएँ लाती है। इसलिए आटा हमेशा चिकना और निशानरहित होना चाहिए, और उसे बनाते समय मन में शुद्ध संकल्प होना चाहिए कि यह अन्न पूरे परिवार के लिए सुखद फल लाए।

पहले के समय में एक बहुत सुंदर परंपरा थी — पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं था, बल्कि ऊर्जा संतुलन का एक सूक्ष्म नियम था। गाय को पहली रोटी देने का अर्थ है — अन्न की पवित्रता को ब्रह्मांड में समर्पित करना। यह कर्म हमारे भीतर कृतज्ञता और सेवा भाव जगाता है। वहीं आखिरी रोटी कुत्ते को देने का अर्थ है — राहु और केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत करना। जो परिवार यह नियम निभाते हैं, उनके घर में भोजन की कमी कभी नहीं होती, और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा सदैव प्रवाहित रहती है।

कई लोग रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा करके रख देते हैं। यह साधारण आदत वास्तव में बड़ा वास्तु दोष है। तवा अग्नि का प्रतीक होता है — और अग्नि शक्ति को उल्टा रखना “अग्नि देवता” का अपमान माना गया है। ऐसा करने से घर में कलह, क्रोध और रोगों की वृद्धि होती है। इसलिए जब भी तवा उपयोग के बाद उतारा जाए, तो उसे साफ करके सीधा रख देना चाहिए, ताकि अग्नि का सम्मान बना रहे और रसोई में सकारात्मकता बनी रहे।

रोटी परोसते समय एक और अद्भुत नियम बताया गया है — थाली में कभी तीन रोटियाँ एक साथ नहीं रखनी चाहिए। यह संख्या राहु से जुड़ी मानी जाती है, जो भ्रम और अस्थिरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार तीन रोटियाँ एक साथ खाता है, उसकी सेहत बिगड़ने लगती है और घर के वातावरण में अनचाही बहसें बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमेशा दो या चार रोटियाँ परोसनी चाहिए, लेकिन तीन कभी नहीं।

इसके अलावा रोटी हमेशा थाली में रखकर ही परोसनी चाहिए, हाथ में नहीं। हाथ में रोटी देना न केवल अशिष्टता दर्शाता है बल्कि भोजन की ऊर्जा को भी बाधित करता है। भोजन ग्रहण करना एक पवित्र कर्म है, इसलिए उसे हमेशा आदर और शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। रोटी से जुड़ा यह पूरा विज्ञान हमें यह सिखाता है कि अन्न में सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि कर्मफल की ऊर्जा भी निहित होती है। जिस भावना से हम रोटी बनाते हैं, वही भावना हमारे घर के वातावरण में फैलती है। अगर हम उसे श्रद्धा, प्रेम और आभार से बनाते हैं तो घर में समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों स्थायी रूप से बने रहते हैं। लेकिन अगर हम उसे गुस्से या लापरवाही में बनाते हैं, तो वही ऊर्जा घर के रिश्तों और मनोभावों में उतर आती है।

इसलिए अगली बार जब आप आटा गूंथने बैठें, तो याद रखें — आप केवल रोटी नहीं बना रही हैं, आप अपने घर की किस्मत गढ़ रही हैं। जब तवा गर्म हो, तो आपका मन शांत हो। जब रोटी फूल रही हो, तो आपका दिल कृतज्ञता से भरा हो। यही वह क्षण होता है जब अन्न, अग्नि और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं — और वही घर को स्वर्ग बना देता है।

रोटी केवल शरीर का आहार नहीं, वह आत्मा की प्रसन्नता है। वह हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि सोने-चांदी में नहीं, बल्कि उस गरम, नरम, स्नेहभरी रोटी में छिपी है — जो प्रेम से बनाई जाए और आभार से खाई जाए।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नोटरी के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए, नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया

गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विधि राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया सहभागी हुए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कानूनी प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी तथा ऑनेस्टी स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी की भूमिका महत्वपूर्ण है
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है
- सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमत्री का लक्ष्य

- दस्तावेज अपलोड करने तथा आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन, समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी

- नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन होने से पर्यावरण की रक्षा होगी, पेपरलेस गवर्नेंस को वेग मिलेगा

- गुजरात के इतिहास में पहली बार 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी के रूप में नियुक्ति दी गई : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विधि विभाग तथा गुजरात बार काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नोटरी (लेख्य प्रमाणक) के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को बुधवार को गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्री पटेल ने राज्य में ई-नोटरी सिस्टम विकसित करने के लिए नोटरी पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साधारण व्यक्ति के हित को तथा उसकी सरलता को ईज ऑफ लिविंग के केन्द्र में रखा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया या याजोनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट का शासन मंत्र अपनाया है। यह कार्यक्रम गुजरात के विधि जगत में आज उसी मंत्र को साकार करने वाला अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विधि (कानून) का शासन महत्वपूर्ण नींव है। प्रधानमंत्री ने कानून के शासन के लिए समयानुरूप कानून प्रस्तुत करने का भगीरथ कार्य किया है। उन्होंने अंग्रेजों के समय के अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर कानूनी प्रक्रिया सरल बनाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है। ट्रिपल तलाक निषेध, धारा 370 निर्मूलन तथा भारतीय न्याय संहिता का सुचारु कार्यान्वयन उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में विश्वास, सुरक्षा तथा प्रामाणिकता स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी के रूप में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री पटेल ने जोड़ा कि वैधानिक प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास का निर्माण करने के लिए दस्तावेजों की ऑथेंटिसिटी का दायित्व नोटरी के सिर होता है। नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिलती है तथा कोर्ट एवं अन्य स्थानों पर इन दस्तावेजों की स्वीकृति सरल बनने से लोगों का ईज ऑफ डूइंग भी बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आम आदमी को मिलने वाली सेवा सुविधाओं में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया युग शुरू करवाया है। सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने डिजिटल भारत अंतर्गत डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं की पारदर्शी पहुँच को सुनिश्चित किया है। उनके दिशादर्शन में वैधानिक व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर बल दिया गया है।

उन्होंने नोटरी पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज गुजरात में शुरू हुआ नोटरी पोर्टल प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने वाला एक और कदम है। नए पोर्टल के फलस्वरूप नोटरी की नियुक्ति तथा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। सभी को समान एवं न्यायी अवसर भी मिलेंगे। दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे नोटरी की सेवा लेने में लगने वाले समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि नोटरी पोर्टल से लीगल डॉक्यूमेंट भविष्य में सुरक्षित एवं प्रमाणित करने के साथ वर्षों तक उनका सेंट्रल रिकॉर्ड संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध ढंग से डिजिटलाइजेशन होने से कागज का उपयोग घटेगा व पर्यावरण की रक्षा होगी, जिससे पेपरलेस गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को वेग मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने नवनियुक्त नोटरी के रूप में चयनित अधिवक्ताओं को अभिनंदन देते हुए कहा कि गुजरात के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यानी 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी बनाने का भगीरथ कार्य मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

श्री संघवी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात में नोटरी के 2900 पदों की संख्या दुगुनी करके आज 6000 की गई है, जिससे भविष्य में बड़ी संख्या में वकीलों को इसका लाभ मिलेगा। आज नोटरी के लिए ई-पोर्टल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस ई-पोर्टल के माध्यम से साधारण नागरिकों के समय की बचत होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं से मुवक्किल के हित के साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते हुए तेजी से न्याय दिलाने के लिए सहयोग देने की अपील की।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे गौहत्या नियंत्रण तथा गौमाता रक्षा के लिए जिस कानून को लाए, वह ऐतिहासिक निर्णय था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन से कल एक ऐतिहासिक फैसला आया। अमरेली में गौहत्या करने वाले को इस अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा हुई है, जो श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में लाए गए कड़े कानून का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में पोक्सो के मामलों में 24 घण्टों के भीतर चार्जशीट फाइल करने में सफलता मिली है। एक महीने में 15 से अधिक मामलों में चार्जशीट हुई, जिसमें कइयों को फाँसी तथा आजीवन कारावास की सजा हुई है।

विधि राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया ने कहा कि नोटरी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कानूनी प्रक्रिया में विश्वास स्थापित करने वाले हैं। नोटरी के कार्य से ठगी होने की आशंकाओं में कमी आती है। नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिलती है। उचित ढंग से तथा योग्य पक्षकार द्वारा जब दस्तावेज बनाए जाते हैं, तब नोटरी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विशेषकर; संपत्ति के दस्तावेजों, बिक्री आदि दस्तावेजों में नोटरी के हस्ताक्षर-मुहर से कानूनी प्रक्रिया आसान बनती है। आज जब लगभग 1500 नोटरियों को एक साथ नियुक्ति मिली है, तब लोगों की सुविधा में वृद्धि होगी। नोटरी द्वारा पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भी लोगों को कानूनी सुविधाएँ प्राप्त करने में सरलता रहेगी। इसके साथ श्री वेकरिया ने नवनियुक्त नोटरियों से लोगों के नोटरी पर रहे विश्वास को बनाए रखने की अपील की।

प्रारंभ में स्वागत संबोधन में बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री जे. जे. पटेल ने कहा कि देश में बार काउंसिल की सहायता करने का प्रारंभ गुजरात में 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए का अनुदान देकर तथा ई-लाइब्रेरी की सुविधा के माध्यम से किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात सरकार ने बार काउंसिल को विभिन्न कामकाज के लिए अब तक 28 करोड़ रुपए की भारी राशि की सहायता दी है। दूसरी ओर हाल ही में केन्द्र सरकार ने 8086 अधिवक्ताओं को नोटरी की उपाधि से सम्मानित किया, जबकि आज राज्य सरकार द्वारा और 1500 वकीलों को नोटरी प्रमाणपत्र दिए जाने से अब राज्य में कुल 9500 अधिवक्ता गुजरात के नोटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव जनता के कार्यों में आसानी से देखने को मिल रहा है। आज हर गाँव में जन सेवा के लिए नोटरी उपलब्ध है।

इस समारोह में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, संयुक्त सचिव श्री एच. एस. वर्मा, महाधिवक्ता श्री कमल त्रिवेदी, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू) के पंजीयक श्री नितिन मलिक तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के विश्वामित्री – डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 14 नवम्बर 2025 को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1. ट्रेन नं 69201 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
2. ट्रेन नं 69202 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
3. ट्रेन नं 69203 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
4. ट्रेन नं 69204 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
5. ट्रेन नं 69205 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
6. ट्रेन नं 69206 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
7. ट्रेन नं 59117 प्रतापनगर – छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
8. ट्रेन नं 59122 छोटाउदैपुर - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
9. ट्रेन नं 59125 प्रतापनगर – छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
10. ट्रेन नं 59126 छोटाउदैपुर - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
11. ट्रेन नं 59123 प्रतापनगर – जोबट पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
12. ट्रेन नं 59124 जोबट - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी

आंशिक रूप से रद्द

1. 14 नवम्बर 2025 को ट्रेन नं 59118 अलीराजपुर – प्रतापनगर पैसेंजर डभोई तक चलेगी तथा डभोई – प्रतापनगर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
2. 14 नवम्बर 2025 को ट्रेन नं 59121 प्रतापनगर - अलीराजपुर पैसेंजर डभोई से चलेगी तथा प्रतापनगर - डभोई के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

13-14 नवंबर की रात में 4 घंटे के लिए रांधेजा स्थित रेलवे फाटक नं. 15 सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के गांधीनगर हाईवे से मानसा के बीच स्थित रांधेजा रेलवे फाटक नं.15 दिनांक 13-14 नवंबर 2025 की रात में 4 घंटे के लिए सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा।

आदरज मोटी-विजापुर रेलवे लाइन गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित मशीन टेंपिंग कार्य हेतु गांधीनगर हाईवे से मानसा के बीच रांधेजा स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 15 दिनांक 13 नवंबर 2025 को रात्रि 23.00 बजे से 13 नवंबर 2025 को 03.00 बजे तक 4 घंटे के लिए सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा

2013 में तलाक के बाद से कोई संपर्क नहीं: जफर हयात

(जीएनएस)। कानपुर। दिल्ली में हुए हालिया बम धमाके के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के नाम के सामने आने के बाद उनके पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी। डॉ. हयात ने स्पष्ट किया कि 2013 में तलाक होने के बाद से उनका शाहीन से कोई भी संपर्क नहीं रहा और उन्हें उसके निजी जीवन या हाल की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है।

डॉ. शाहीन, जिन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, लखनऊ की रहने वाली हैं और कभी कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रही थीं। जांच एजेंसियों को शाहीन के कानपुर से जुड़े कुछ सुराग मिले थे, जिसके बाद विशेष टीम ने कानपुर में उसकी जांच की।

डॉ. जफर हयात, जो वर्तमान में कानपुर के केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं, ने बताया कि उनकी शादी 2003 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। शादी के कुछ वर्षों बाद ही शाहीन विदेश—विशेषकर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप—में बसने का दबाव डालने लगी। मतभेद बढ़ने के कारण 2013 में तलाक हुआ और तब से दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा। उन्होंने कहा, "तलाक के बाद से न तो कोई बातचीत हुई और न ही मुलाकात। उसके निजी जीवन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा है।"

डॉ. हयात ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि शाहीन आतंकी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई या उसके पास हथियार कैसे पहुंचे।

दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने कई शहरों में छापेमारी की थी। इसी कार्रवाई के दौरान डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी ने मेडिकल समुदाय में भी सनसनी फैला दी। जांच टीम अब शाहीन के नेटवर्क और संपर्कों की गहन पड़ताल में जुटी हुई है, ताकि उसके संभावित सहयोगियों और गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

बिहार चुनाव के बाद नेपाल-भारत सीमा खुली, सुरक्षा कड़ी बरकरार

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीन दिनों तक बंद रही नेपाल-भारत सीमा बुधवार से सामान्य रूप से खुल गई, लेकिन सुरक्षा के स्तर में कोई ढील नहीं दी गई। यह कदम चुनावी बंद के बाद नियमित गतिविधियों को बहाल करने के लिए लिया गया है, लेकिन दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट और बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

सशस्त्र पुलिस के प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापा ने बताया कि नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल ने सभी प्रमुख सीमा नाकों पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है। इस कदम का उद्देश्य बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के बीच अवांछित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद सीमाओं को खोलने का मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा में कोई ढील दी गई है।

सीमा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की फोटो आईडी की जांच की जा रही है, जबकि वाहनों की भी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। सीमा पार करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन में नशीले पदार्थ, हथियार, फरार कैदी या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सामग्री पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा संदिग्धों को पकड़कर संबंधित विभागों को सौंपने की व्यवस्था भी लागू है।

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस बार चुनाव और हाल की सुरक्षा घटनाओं के मद्देनजर नेपाल-भारत सीमा पर लगातार सतर्कता बरती जाएगी। यही नहीं, सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस गश्त और रडार निगरानी को बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। इस बीच स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सीमा पार करते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव और सुरक्षा घटनाओं के बीच सीमा सुरक्षा बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह न केवल अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को भी मजबूत बनाए रखेगा।

सोनभद्र में जमीन के विवाद ने ली जान, बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या की

(जीएनएस)। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद ने हृदय विदारक रूप ले लिया जब एक छोटे बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, यह विवाद 10 बिस्सा जमीन के अधिकार को लेकर चला आ रहा था, और बुधवार को यह झगड़ा घातक परिणति में बदल गया।

क्षेत्राधिकारी राज सोनकर ने बताया कि बकवार गांव निवासी लालधारी (70 वर्ष) ने अपनी 20 बिस्सा जमीन में से 10-10 बिस्सा अपने दोनों बेटों, बैजनाथ और अमरनाथ के नाम कर दी थी। इसके बावजूद लालधारी ने 10 बिस्सा अपने पास रख ली। लालधारी अपने बड़े बेटे बैजनाथ के साथ रहता था, जिससे छोटे बेटे अमरनाथ को आशंका थी कि पिता भविष्य में अपनी जमीन भी बड़े बेटे के नाम कर देंगे। इसी डर और तनाव के चलते दोनों भाइयों में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था।

बुधवार को भी विवाद तेज हो गया और अमरनाथ ने क्रोध में आकर कुल्हाड़ी से पिता लालधारी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बैजनाथ ने पुलिस को बताया कि इस हत्या का कारण जमीन को लेकर चले विवाद से उत्पन्न तनाव था।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपित अमरनाथ फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस ने जमीन के बंटवारे और पारिवारिक तनाव से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल शुरू कर दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि परिवारिक संपत्ति के विवाद अक्सर इस तरह की हिंसक घटनाओं को जन्म देते हैं, और यह घटना इस बात की हृदय विदारक पुष्टि करती है कि छोटी-छोटी आपसी गलतफहमियां और लालच कभी-कभी जानलेवा संघर्ष का रूप ले लेती हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस मामले में आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और परिवारों को अपने संपत्ति विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की सलाह दी जा रही है।

भारत-सऊदी अरब आर्थिक साझेदारी को नई गति, पीयूष गोयल ने निवेश और व्यापार विस्तार पर की चर्चा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल-फलीह के बीच बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और सशक्त बनाने और निवेश के अवसर बढ़ाने पर गहन विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप सेक्टर में साझेदारी को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। गोयल ने कहा कि भारत-सऊदी साझेदारी "आपसी विश्वास, साझा विकास और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि" पर आधारित है। दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने निवेश सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्रों में संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

इस बैठक के साथ ही हाल ही में रियाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और सऊदी संस्कृति मंत्री प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान अल सऊद के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस MoU के तहत कला, विरासत, संगीत और साहित्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 41.88 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का योगदान 4.5 अरब डॉलर रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से न केवल दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी, बल्कि ऊर्जा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

इसके अलावा, बैठक में निवेशकों को प्रोत्साहित करने और नई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नियमित बैठकें और संवाद जारी रखा जाएगा। विश्लेषकों के अनुसार, इस पहल से भारत-सऊदी अरब के बीच ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सहयोग को नई गति मिलेगी और आने वाले वर्षों में व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

अमूमन आम आदमी को बड़ी राहत: अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 0.25 प्रतिशत पर पहुंची

(जीएनएस)। नई दिल्ली। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच आम जनता को राहत देने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई दर (Consumer Price Index आधारित) घटकर 0.25 प्रतिशत पर आ गई है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती, सब्जियों और फलों की कीमतों में नरमी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की महंगाई में संतुलन के कारण हुई है। तुलना करें तो अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत थी, जबकि सितंबर 2025 में यह 1.44 प्रतिशत पर थी। अक्टूबर 2025 में इस दर में 119 आधार अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह वर्तमान सीपीआई श्रृंखला का सबसे निचला स्तर बन गया। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, यह संकेत है कि देश में मुद्रास्फीति का दबाव फिलहाल कम हुआ है और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदना आसान हुआ है। खाद्य महंगाई पर नजर डालें तो अक्टूबर 2025 में यह घटकर 5.02 प्रतिशत पर पहुंच गई। एनएसओ ने बताया कि तेल, वसा, अनाज, अंडे, सब्जी और फलों की कीमतों में गिरावट, परिवहन व संचार की लागत में संतुलन और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण कुल महंगाई दर में यह गिरावट आई है। GST दरों में कटौती का भी सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में नरमी देखने को मिली।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति आर्थिक गतिविधियों के लिए भी अनुकूल है। उपभोक्ता खरीदारी के प्रति उत्साहित होंगे, जिससे बाजार में मांग बनी रहेगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कई विश्लेषक यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि मौसमी बदलाव और वैश्विक कच्चे तेल व खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भविष्य में महंगाई में बढ़ोतरी संभव है। सरकारी और निजी संस्थानों के अनुसार, यह वर्तमान स्थिति उपभोक्ताओं के लिए एक संयोग है कि बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में हैं। इस दौर में घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और नागरिकों की खरीद क्षमता को बनाए रखना मुख्य चुनौती है। आने वाले महीनों में इस दर पर नजर रखी जाएगी, ताकि यदि कोई बदलाव आए तो समय रहते नीतिगत कदम उठाए जा सकें। इस डेटा के प्रकाश में आम आदमी को राहत मिली है, क्योंकि कई सालों के बाद जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता और महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान लगातार बना रहे तो उपभोक्ता खर्च और आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी: आतंकी मोहिउद्दीन के घर से मिला खतरनाक रसायन, साइनाइड बनाकर तैयार हो रहा था जहर

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की जांच में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांधीनगर से गिरफ्तार आतंकी अहमद मोहिउद्दीन सैयद के हैदराबाद स्थित घर से भारी मात्रा में जहरीला रासायनिक पदार्थ और साइनाइड बनाने का कच्चा माल बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक, यह रसायन विस्फोटक या जैव-रासायनिक हमले में इस्तेमाल किया जा सकता था। एटीएस ने इसे जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

गुजरात एटीएस ने कुछ दिन पहले गांधीनगर के अडालज इलाके से तीन संदिग्ध आतंकियों — अहमद मोहिउद्दीन सैयद, तारिक रशीद और मोहम्मद अरमान — को गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि मोहिउद्दीन कई महीनों से साइनाइड और अन्य जहरीले रसायनों के प्रयोग कर रहा था। वह एक ऑनलाइन नेटवर्क के ज़रिए यह सब 'रिसर्च' के नाम पर करता था और अपने संपर्कों के माध्यम से रसायन जुटाता था। एटीएस को शक है कि यह रसायन किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश में इस्तेमाल किया जाना था। हैदराबाद से मिले दस्तावेजों में कुछ विदेशी नंबर, लैब नोट्स और ऑनलाइन चैट रिकॉर्ड भी मिले हैं जिनमें रासायनिक तत्वों के संयोजन के तरीकों का विस्तृत विवरण है। जांचकर्ताओं का कहना है कि बरामद सामग्री को देखकर यह स्पष्ट है कि मोहिउद्दीन के पास वैज्ञानिक स्तर की समझ थी और वह किसी प्रशिक्षित नेटवर्क से निर्देश ले रहा था।

गुजरात एटीएस के सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आतंकियों के पाकिस्तान स्थित संगठन से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव जब्त कर लिए गए हैं, जिनमें एन्क्रिप्टेड फाइलें और विदेशी चैट प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। दिल्ली और अहमदाबाद कनेक्शन ने भी जांच को नए मोड़ पर ला दिया है। बताया जा रहा है कि मोहिउद्दीन हाल के महीनों में दिल्ली के आज़ाद मैदान और अहमदाबाद की नरोडा फल मंडी में गया था, जहां उसने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात की थी। जांच एजेंसियां इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि कहीं "कश्मीरी सेब" के कार्गो की आड़ में कोई प्रतिबंधित सामग्री देशभर में भेजने की साजिश तो नहीं रची गई थी।

इस बीच उत्तर प्रदेश और राजस्थान एटीएस की टीमें भी गांधीनगर पहुंच चुकी हैं और गुजरात एटीएस के साथ संयुक्त जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि इस नेटवर्क के किसी भी छोर को छूटने न दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह मॉड्यूल "लो-टेक हाई-इम्पैक्ट" रणनीति पर काम कर रहा था — यानी कम संसाधनों से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की योजना। अब फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद एजेंसियां पूरे मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जांच रिपोर्ट्स को गुप्त रखा गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) से भी तकनीकी सहयोग मांगा गया है। देशभर में रासायनिक पदार्थों की बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी नेटवर्क पर भी विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

भारत में हमलों के लिए हमारी भूमि का उपयोग असंभव: बांग्लादेश बांग्लादेश ने आतंकवाद के आरोपों को सिरे से नकारा

(जीएनएस)। ढाका से आई खबर ने भारत और दक्षिण एशिया के कूटनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। बांग्लादेश सरकार ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफ़िज़ सईद भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए बांग्लादेश की भूमि का उपयोग कर रहा है। ढाका ने इस आरोप को "पूरी तरह निराधार और अस्वीकार्य" बताया है।

बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मंगलवार शाम विदेश मंत्रालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि "भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल असंभव है। हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाया है और इस नीति से कभी समझौता नहीं किया जाएगा।"

हुसैन ने मीडिया रिपोर्टों की आलोचना करते हुए कहा कि "कुछ भी हो जाए, कुछ मीडिया संस्थान बांग्लादेश को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं मानेगा कि बांग्लादेश भारत जैसे पड़ोसी देश के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि को समर्थन देगा।"

उन्होंने दोहराया कि भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा एवं खुफिया सहयोग अत्यंत मजबूत है और दोनों देश सीमा पार अपराध, आतंकवाद, और चरमपंथ के खिलाफ साझा प्रयासों में लगातार जुटे हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या बांग्लादेश में छिपे कुछ चरमपंथी तत्वों का भारत विरोधी नेटवर्क से कोई संबंध है, तो हुसैन ने साफ शब्दों में कहा कि "अगर किसी भी व्यक्ति या समूह के ऐसे संबंध पाए जाते हैं, तो कार्रवाई तत्काल होती है — इस पर बांग्लादेश की नीति बिल्कुल स्पष्ट है।"

इस बीच, वार्ता के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के मुकदमे का भी ज़िक्र आया। हुसैन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ब्रिटेन स्थित दो वकीलों ने हसीना की ओर से संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन "अभी तक यूएन से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।"

हुसैन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश किसी भी देश के पक्ष में झुकाव नहीं रखता। "हम सभी देशों — भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप — के साथ संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। चीन से हथियार खरीद के मुद्दे पर भी हमें किसी अमेरिकी प्रतिबंध की आशंका नहीं है।" बांग्लादेश सरकार की यह सख्त प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब भारत में सुरक्षा एजेंसियां लाल किला विस्फोट और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। इन घटनाओं के बीच ढाका की इस साफ सफाई को कूटनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चे पर बांग्लादेश की भूमिका अब और निर्णायक होती जा रही है।

हर भारतीय को अब मिलेगा ई-पासपोर्ट: विदेश मंत्रालय ने शुरू की नई डिजिटल व्यवस्था

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत अब पासपोर्ट सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा तकनीकी कदम उठाने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि अब से देश में जारी होने वाले सभी पासपोर्ट "ई-पासपोर्ट" होंगे। यह नई व्यवस्था भारतीय पासपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाएगी और नागरिकों को तेज़, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा दस्तावेज़ उपलब्ध कराएगी।

मंत्रालय के अनुसार, ई-पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप होगी, जिसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी — जैसे नाम, जन्मतिथि, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा — एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहेगी। इस चिप की मदद से पहचान की पुष्टि कुछ ही सेकंड में हो जाएगी, जिससे एयरपोर्ट और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में समय की बचत होगी।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पुराने सामान्य पासपोर्ट उनकी वैधता अवधि समाप्त होने तक पूरी तरह मान्य रहेंगे। नागरिकों को उन्हें तुरंत बदलने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, नए आवेदन या रिन्यूअल के दौरान अब केवल ई-पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे।

ई-पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगे। यह न केवल डेटा सुरक्षा को मज़बूत बनाएंगे, बल्कि पासपोर्ट की जालसाजी, नकली पासपोर्ट बनाना या पहचान की चोरी जैसी समस्याओं को भी लगभग असंभव कर देंगे।

यह कदम विदेश मंत्रालय के "पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP V2.0)" और "ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (GPSP V2.0)" के तहत उठाया गया है। PSP V2.0 को देश के 37 पासपोर्ट कार्यालयों, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 450 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। वहीं GPSP V2.0 अब दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से भी संचालित हो रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि ई-पासपोर्ट प्रणाली पासपोर्ट जारी करने की पूरी प्रक्रिया को न केवल तेज़ और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि इससे नागरिकों को "पेपरलेस" और "कैशलेस" सेवा का अनुभव मिलेगा। आवेदन की स्थिति, सत्यापन और वितरण से जुड़ी जानकारी अब पूरी तरह डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी।

ई-पासपोर्ट को "हाइब्रिड पासपोर्ट" भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पारंपरिक दस्तावेज़ और डिजिटल डेटा स्टोरेज — दोनों मौजूद रहेंगे। इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और भारतीय सुरक्षा मुद्रण प्रेस, नासिक द्वारा मिलकर विकसित किया गया है।

विदेश मंत्रालय का यह कदम "डिजिटल इंडिया" मिशन की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में भारत के अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज़ों को पूरी तरह स्मार्ट, सुरक्षित और वैश्विक स्तर का बनाएगा।

दिल्ली विस्फोट: एक और संदिग्ध कार की तलाश

(जीएनएस)। दिल्ली विस्फोट मामले में पुलिस ने अब अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। लाल किले के पास हुए इस भयावह धमाके के बाद जहां पहले एक आई-20 कार को संदिग्ध माना जा रहा था, अब जांच एजेंसियां दूसरी लाल रंग की ईको स्पोर्ट कार की तलाश में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कार घटना से कुछ घंटे पहले आसपास के इलाकों में देखी गई थी। पुलिस को आशंका है कि इस कार का इस्तेमाल संदिग्धों ने विस्फोट से पहले या बाद में भागने के लिए किया हो सकता है। दिल्ली पुलिस की पांच टीमें पूरी राजधानी में छानबीन कर रही हैं। शहर के सभी थानों, पुलिस पोस्टों और सीमाओं पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। खास तौर पर दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इन दोनों राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट भेज दिया है ताकि अगर यह लाल ईको स्पोर्ट कार वहां दिखे तो तुरंत सूचना साझा की जा सके।

जांच में यह खुलासा हुआ कि मुख्य संदिग्धों के पास पहले से एक आई-20 कार थी, जो विस्फोट स्थल के पास खड़ी मिली थी। लेकिन CCTV फुटेज में एक लाल रंग की दूसरी गाड़ी भी कुछ दूरी पर नजर आई थी, जिसके बाद शक और गहरा गया है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह दोनों कारें एक ही नेटवर्क के आतंकियों की थीं या किसी स्थानीय सहयोगी ने इसमें मदद की थी।

इस बीच, केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। एनआईए ने 10 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसकी अगुवाई एडीजी विजय सखारे करेंगे। उनके साथ एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम ने दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो से प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी है ताकि घटनाक्रम की समयरेखा तैयार की जा सके।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वाहन या गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने में दें। पुलिस का कहना है कि राजधानी में सुरक्षा को लेकर फिलहाल उच्चतम सतर्कता बरती जा रही है और हर संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

लाल किला धमाका जांच की पहुंच बंगाल तक, मुर्शिदाबाद में एनआईए की बड़ी छापेमारी

(जीएनएस)। मुर्शिदाबाद/नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला विस्फोट की गूंज अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम थाना क्षेत्र के नीम गांव में तड़के विशेष अभियान चलाकर कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस होने के बाद की गई, जो दिल्ली में गिरफ्तार किए गए मुख्य संदिग्धों में से एक के संपर्क सूची में पाया गया था। एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मौइनुल हसन नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ली। मौइनुल पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली और मुंबई में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करता था। एजेंसी को शक है कि उसी दौरान उसका संपर्क कुछ संदिग्ध नेटवर्क से हुआ। जांच अधिकारी उसके मोबाइल डेटा, बैंक लेन-देन और हालिया कॉल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। एजेंसी को यह भी संदेह है कि वह कुछ लोगों के जरिए धन और सूचनाओं के आदान-प्रदान में शामिल था।

छापेमारी के दौरान एजेंसी ने डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया है। एनआईए सूत्रों के अनुसार, कई और व्यक्तियों के नाम जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें कुछ पड़ोसी जिलों — बहरामपुर और डोमकल — के लोग भी शामिल हैं। इन सभी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया खातों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दिल्ली धमाके की साजिश के सूत्र कहीं बंगाल की जमीन से तो नहीं जुड़े हैं।

इस बीच, दिल्ली में चल रही जांच में अब तक 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। एजेंसियों ने चार डॉक्टरों की भी तलाश तेज कर दी है, जिन पर विस्फोट में इस्तेमाल हुए रासायनिक मिश्रण की तैयारी में मदद करने का संदेह है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश के बरेली में और दूसरा संभवतः कोलकाता में छिपा हो सकता है।

मुर्शिदाबाद का अतीत भी एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। यह इलाका पहले भी आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है। इसी वर्ष फरवरी में एनआईए ने यहां से 'अंसारुल्ला बांग्ला टीम' से जुड़े कई आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में हथियार, संदिग्ध नक्शे और डिजिटल डेटा बरामद किए गए थे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि एनआईए की बुधवार की कार्रवाई के दौरान पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया था। सुबह 5 बजे से लेकर करीब तीन घंटे तक एजेंसी ने घरों की तलाशी ली। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं और ग्रामीणों से पूछताछ की है।

अधिकारियों का कहना है कि जांच का दायरा अब पूर्वी भारत के कुछ अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया जा सकता है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली धमाका एक अलग घटना थी या फिर इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की संगठित साजिश थी। फिलहाल एनआईए ने मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

तुर्किये में सैन्य विमान हादसा, बीस सैनिकों की दर्दनाक मौत — जॉर्जिया की पहाड़ियों में गिरा सी-130 बी विमान, अजरबैजान से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद नियंत्रण खो बैठा

(जीएनएस)। अंकारा/त्बिलिसी। तुर्किये और जॉर्जिया की सीमाओं के बीच मंगलवार देर रात हुए एक भयानक सैन्य हादसे ने पूरे तुर्की राष्ट्र को शोक में डुबो दिया। तुर्किये वायुसेना का सी-130 बी मॉडल मालवाहक विमान जॉर्जिया के पूर्वी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 20 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह विमान अजरबैजान से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद संपर्क खो बैठा और फिर जॉर्जिया के सिग्नाही क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ों में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि विमान के टकराते ही उसमें आग लग गई और पूरा मलबा पहाड़ी ढलानों में बिखर गया।

रक्षा मंत्रालय ने बुधवार सुबह एक बयान जारी कर कहा कि यह विमान एक नियमित सैन्य अभियान का हिस्सा था और सैन्य सामग्री तथा कर्मियों को लेकर जॉर्जिया के ऊपर से उड़ान भर रहा था। मंत्रालय के मुताबिक, विमान ने उड़ान भरने के लगभग पाँच किलोमीटर बाद ही नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वह तेजी से नीचे गिरा और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। हादसे के बाद राहत दलों को घटनास्थल तक पहुंचने में कई घंटे लग गए, क्योंकि वह इलाका घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से घिरा हुआ था।

जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि विमान का मलबा सिग्नाही जिले के पहाड़ी इलाके में मिला है। राहत और बचाव दल ने स्थानीय पुलिस व सेना के सहयोग से शवों की खोज अभियान शुरू किया और अब तक सभी 20 शव बरामद किए जा चुके हैं। जॉर्जिया सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, जबकि क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गई है ताकि किसी और नुकसान से बचा जा सके।

तुर्किये और जॉर्जिया दोनों ने संयुक्त रूप से एक विशेष जांच टीम गठित की है जो हादसे के असली कारणों की पड़ताल करेगी। प्रारंभिक रिपोर्टों

में तकनीकी खराबी या खराब मौसम को संभावित वजह बताया गया है, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी आतंकी या तोड़फोड़ की संभावना से भी इंकार नहीं कर रही हैं। जांच अधिकारी विमान के ब्लैक बॉक्स और डेटा रिकॉर्डर की तलाश में जुटे हैं ताकि दुर्घटना के कुछ पल पहले की स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सके।

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। वे अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए देश के लिए प्राण न्योछावर कर गए। हम उनके परिवारों के साथ हैं और यह राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।" राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि हादसे की विस्तृत जांच कर दोषियों की पहचान की जाए, चाहे वे तकनीकी लापरवाही के लिए ही क्यों न जिम्मेदार हों।

अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भी तुर्की सरकार को संवेदना संदेश भेजा और कहा कि "यह सिर्फ तुर्की का नहीं, बल्कि अजरबैजान का भी नुकसान है। हमारे सैनिकों के बलिदान से दोनों देशों के बीच भाईचारे का बंधन और भी मजबूत होगा।"

सी-130 बी विमान, जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है, दुनियाभर की सेनाओं में इस्तेमाल होता है और इसे सबसे विश्वसनीय सैन्य परिवहन विमानों में गिना जाता है। यह सैनिकों और सैन्य सामग्री के साथ-साथ राहत और आपदा अभियानों में भी प्रयुक्त होता है। हालांकि तुर्की वायुसेना के पास मौजूद सी-130 विमानों का अधिकांश बेड़ा कई दशकों पुराना है और उसकी तकनीकी स्थिति पर विशेषज्ञ पहले भी सवाल उठा चुके हैं।

जॉर्जिया के नागरिक उड्डयन विभाग ने बताया कि हादसे में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा कारणों से सिग्नाही और आसपास के हवाई मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। क्षेत्र में बचाव कार्य जारी है और स्थानीय प्रशासन ने वहां के ग्रामीणों से क्षेत्र में प्रवेश न करने की अपील की है।

यह हादसा तुर्की वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया, काकेशस और भूमध्य सागर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुर्घटना तुर्की के सैन्य ढांचे में तकनीकी सुरक्षा और रखरखाव मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार अब इस घटना के बाद अपने पुराने विमानों के आधुनिकीकरण और रखरखाव की नीति पर पुनर्विचार करने की संभावना पर विचार कर रही है।

पूर्वी एशियाई कंपनियों का मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश, भारत में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य उपकरण केंद्र

(जीएनएस)। नोएडा। उत्तर प्रदेश के यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क अब अंतरराष्ट्रीय निवेश का नया केंद्र बनने जा रहा है। पूर्वी एशियाई देशों — जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की अग्रणी कंपनियां इस पार्क में बड़े पैमाने पर निवेश करने की योजना बना रही हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 13 नवंबर को जापान के चेक अगुआई से उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल यमुना प्राधिकरण मुख्यालय पहुंचेगा। पार्क के प्रशासनिक भवन में आयोजित इस त्रिपक्षीय बैठक में लगभग 20 विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि जापान की मेडिकल एक्सीलेंस कंपनी के सीईओ केंजी शिबुया के नेतृत्व में आने वाला यह प्रतिनिधिमंडल पार्क का निरीक्षण करेगा। बैठक में भारतीय कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि विदेशी साझेदारों के साथ तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन और नवाचार का ढांचा तैयार किया जा सके।

बैठक में मेडिकल एक्सीलेंस जापान, इकॉनमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया (ERIA) और यमुना प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर का प्रस्ताव रखा गया है। इस समझौते के बाद अन्य एशियाई देशों की कंपनियों के लिए भी निवेश के अवसर खुलेंगे और पार्क में वैश्विक स्वास्थ्य उपकरण उद्योग के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा। साथ ही, पार्क में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जापान के सहयोग से 'आस्का लैब' (ASKA Lab) की स्थापना की जाएगी। यह लैब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करेगी और मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित होगी। अधिकारी मानते हैं कि इस लैब के माध्यम से भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ एक साथ मिलकर नई तकनीकों और उपकरणों का विकास कर सकते हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य तकनीक उद्योग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस पहल से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारत की स्वास्थ्य उपकरण निर्माण क्षमता में भी बड़ा सुधार आएगा। पूर्वी एशियाई निवेशकों के जुड़ाव से मेडिकल डिवाइस पार्क अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन, गुणवत्ता और नवाचार के केंद्र के रूप में उभर सकता है, जो पूरे क्षेत्र की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देगा।

आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, विज्ञान और तकनीक में नई क्रांति की उम्मीद

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है, जो चुंबकीय क्षेत्रों की त्रि-आयामी (3डी) छवियों का निर्माण कर सकता है। यह माइक्रोस्कोप न्यूरोसाइंस, मटेरियल साइंस, सेमीकंडक्टर चिप परीक्षण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है।

इस उपकरण का विकास राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत किया गया है और इसके साथ ही भारत को इस तकनीक का पहला पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह माइक्रोस्कोप चिप की अंदरूनी परतों में सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों की 3डी मैपिंग कर सकता है। इस तकनीक के माध्यम से न केवल उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्वायत्त प्रणालियों के परीक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि न्यूरोसाइंस और जैविक इमेजिंग में भी नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

इस उपलब्धि को 'एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव' में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के. सूद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंडिकर की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह उपकरण पारंपरिक माइक्रोस्कोप की तुलना में कई गुना अधिक सटीक है और नैनोमीटर स्तर पर 3डी चुंबकीय क्षेत्र की छवि बनाने में सक्षम है।प्रोफेसर कस्तूरी साहा और उनकी टीम द्वारा विकसित यह माइक्रोस्कोप नाइट्रोजन वैकेंसी (NV) केंद्रों पर आधारित है। NV केंद्र हीरे में नाइट्रोजन परमाणु के पास मौजूद एक रिक्त स्थान होता है, जो कमरे के तापमान पर भी मजबूत क्वांटम गुण प्रदर्शित करता है। इस तकनीक के माध्यम से चुंबकीय, विद्युत और तापीय परिवर्तनों का बेहद सटीक मापन किया जा सकता है। इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग 3डी चिप आर्किटेक्चर, क्रायोजेनिक प्रोसेसर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक घटकों और उन्नत तकनीकी घटकों के परीक्षण में किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे की टीम अब इस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग आधारित इमेजिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर काम कर रही है। इस नए एकीकृत प्लेटफॉर्म से उन्नत चिप परीक्षण, जैविक इमेजिंग, भूवैज्ञानिक चुंबकीकरण अध्ययन और अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों में नई दिशा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपकरण भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने में मदद करेगा।

आईआईटी बॉम्बे की इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने क्वांटम फिजिक्स और हाईटेक माइक्रोस्कोपिक रिसर्च में अपनी तकनीकी क्षमता का परिचय दिया है। देश के वैज्ञानिक अब न्यूरोसाइंस, मटेरियल साइंस, सेमीकंडक्टर रिसर्च और अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में खुद के विकसित उपकरणों का उपयोग कर नवाचार कर सकेंगे, जो आने वाले वर्षों में विज्ञान और तकनीक में नई क्रांति की नींव रखेगा।